उत्तर प्रदेश जागरण

नहीं बढ़ेंगे जमीन के रेट, 4260 करोड़ का बजट मंजूर

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव हुए पास, सेक्टरों के विकास पर 376 करोड़ रुपये खर्च होंगे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेनो में आशियाना बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण बोर्ड ने संपत्तियों की दरें न बढ़ाने का फैसला किया है। प्राधिकरण हर वर्ष अप्रैल में अपनी संपत्तियों की दरों में वृद्धि करता है। अप्रैल में चुनाव आचार संहिता लगने पर शुक्रवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई।

अटकलें लगाई जा रही थी कि दस से पंद्रह फीसद तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने भूखंडों की प्रचलित दरों को ही यथावत रखा है। मार्च 2020 तक जमीनों की दरें नहीं बढ़ेंगी। शहर में विकास की गति को और रफ्तार देने के लिए बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में 4260.40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। गत वित्तीय वर्ष के मुकाबले यह 17 फीसद अधिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्राधिकरण चेयरमैन डा. अनूप चंद्र पांडे व सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि बजट का बड़ा हिस्सा जमीन अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआइसी) के लिए प्राधिकरण किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदेगा। अन्य योजनाओं के लिए भी किसानों से जमीन ली जाएगी। इसके अलावा बैंकों का कर्ज भी कम किया जाएगा। शहरी सेवा व ग्राम विकास के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्राधिकरण अपने हिस्से की धनराशि में से 300 करोड़ रुपये और देगा। शुक्रवार को प्राधिकरण बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो के लिए भी प्राधिकरण ने अपने हिस्से की धनराशि में से 100 करोड़ रुपये और जारी को स्वीकृति प्रदान की। शहर के आंतरिक और बाहरी विकास पर 431 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे। सेक्टरों के विकास पर 376 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस धनराशि से सेक्टरों के अंदर विकास कार्य किए जाएंगे। गांवों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए भी प्राधिकरण बोर्ड ने 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया। उद्यान विभाग के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

आवंटियों को मिलेगा ओटीएस योजना का लाभ: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में डिफाल्टर आवंटियों को राहत देने के लिए वन टाइम शेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) का प्रस्ताव रखा गया था। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी तरह की योजनाओं के सैकड़ों आवंटियों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

ग्रेनो प्राधिकरण का कुल बजट	4260 .40 करोड़
सेक्टरों के विकास पर खर्च होंगे	376 .40 करोड़
गांवों के विकास पर खर्च होंगे	200 करोड़
उद्यान पर खर्च होंगे	20 करोड़

ई-ऑक्शन से भूखंडों का होगा आवंटन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वाणिज्यिक भूखंडों की अब ई-आक्शन के माध्यम से भूखंडों का आवंटन करेगा। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड से मंजूरी के बाद प्राधिकरण पहली बार इस व्यवस्था को लागू करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन व मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के अधिकांश वाणिज्यिक भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। खाली भूखंडों के आवंटियों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें निर्माण कार्य पूरा कर कंप्लीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए समय दिया गया है। इसके अलावा कुछ आवंटियों ने वाणिज्यिक भूखंड सरेंडर कर दिए हैं या प्राधिकरण ने उनका आवंटन किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया है। ऐसे भूखंडों के आवंटन के लिए प्राधिकरण ई-आक्शन का सहारा लेगा।

एक्वा लाइन का चार किलोमीटर का होगा विस्तार

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते मुख्य सचिव व ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ .अनूप चंद्र पांडे दाएं से दूसरे ● जागरण

ग्रेटर नोएडा स्थित कॉमर्शियल बेल्ट के सामने से गुजरती मेट्रो ● जागरण

जासं, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा मेट्रो डिपो से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन और वहां प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) तक करीब चार किलोमीटर एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसकी फिजीबिलटी रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव को अनुमोदित कर शासन के पास भेज दिया गया है।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा से बड़ी संख्या में लोग नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम व फरीदाबाद नौकरी करने जाते हैं। इनके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो फिट नहीं बैठ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को उम्मीद थी कि एक्वा मेट्रो के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर की आवाजाही और बेहतर होगी। नौकरीपेशा लोग ग्रेटर नोएडा में बसने को प्राथमिकता देंगे। लेकिन प्राधिकरण की उम्मीद पूरी नहीं हुई। एक्वा मेट्रो के रूट व ब्लू लाइन मेट्रो से सीधे कनेक्टिविटी न होने के कारण काफी कम यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। इसलिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक्वा मेट्रो को सीधे डीएमआरसी की मेट्रो लाइन से लिंक करने की योजना को शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 114वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी। इससे दिल्ली, गुरुग्राम की ओर आने-जाने वालों को ग्रेटर नोएडा पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। आवाजाही में समय भी कम लगेगा।

जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए भी होगा फायदेमंद : जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्टिविटी देने की योजना है। एक्वा मेट्रो के नॉलेज पार्क दो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट मेट्रो को लिंक करने की योजना है। एयरपोर्ट तक यात्रियों को कम से कम समय में पहुंचाने के लिए एक्वा मेट्रो को ब्लू लाइन मेट्रो से सीधे लिंक करना जरूरी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रस्ताव से नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो को भी फायदा मिलेगा। दिल्ली की ओर से आने वाले यात्री कम समय में सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच चारों तरफ से लिंक हो जाएगी मेट्रो : नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो का ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी विस्तार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए एनएमआरसी सर्वे करा रहा है।

बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से सीधे नोएडा के बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा से बोड़ाकी तक भी मेट्रो आएगी। इससे नोएडा व ग्रेटर नोएडा के बीच चारों तरफ से मेट्रो लाइन एक-दूसरे से जुड़ जाएगी।

पहले भी बनी थी डीपीआर

एक्वा मेट्रो को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के समानांतर मजेंटा लाइन से जोड़ने के लिए पूर्व में भी डीपीआर तैयार हुई थी। ओखला बर्ड सैंक्चुअरी मेट्रो स्टेशन से इसे सेक्टर 142 पर एक्वा मेट्रो स्टेशन से लिंक करने के लिए करीब 11 किमी लंबा ट्रैक बनना था। लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को रद कर दिया गया। एक्वा मेट्रो के अब बोटेनिकल गार्डन मेट्रो लाइन में सीधे लिंक होने से एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित कंपनियों व शिक्षण संस्थानों के हजारों कर्मचारियों व छात्रों को फायदा होगा।

औद्योगिक भूखंड आवंटियों को मिली राहत

जासं, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने औद्योगिक भूखंड योजना के आवंटियों को भी बड़ी राहत दी है। सेक्टर 11 को छोड़कर अन्य औद्योगिक सेक्टरों में जिन आवंटियों को 30 सितंबर 2011 से पहले भूखंडों का आवंटन हुआ था, उन्हें लीज डीड कराने के लिए तीन माह का समय और दिया गया है। योजना के आवंटियों को 31 जनवरी 2018 तक आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री करानी थी। प्राधिकरण बोर्ड ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 31 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ भूखंडों की रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया है।

बिल्डरों को भी दिया एक और मौका

प्राधिकरण बोर्ड ने खरीदारों को उनके फ्लैट दिलवाने के लिए बिल्डरों को भी राहत प्रदान की है। करीब 60 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनमें 50 हजार फ्लैट खरीदार है। फ्लैटों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। प्राधिकरण की किस्तों का भी भुगतान नहीं किया है। ऐसे में प्राधिकरण भूखंड आवंटन रद कर सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे दस हजार मकान

जासं, ग्रेटर नोएडा : निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार मकान बनाए जाएंगे। 23 व 29 वर्ग मीटर में बिल्डर मकानों का निर्माण करेंगे। इसके बदले में उन्हें अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) दिया जाएगा। जमीन के कुछ हिस्से पर बिल्डर को कॉमर्शियल गतिविधि करने की भी छूट मिलेगी।

मनपसंद पाठ्यक्रम संचालन को मिली मंजूरी

जासं, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने शैक्षिक संस्थान मालिकों को बड़ी राहत दी है। संस्थानों में अब वे अपनी पंसद के हिसाब से पाठ्यक्रम संचालित कर सकेंगे। पाठ्यक्रम बदलते समय संस्थागत आवंटियों को प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लेना पड़ेगा। तकनीकी व प्रबंधन के छात्र न मिलने की वजह से बंदी के कगार पर पहुंचे कालेजों में अब 12 वीं तक की कक्षाएं भी संचालित हो सकेंगी। इससे संस्थानों में ताला लगने से बच जाएगा। शहर में संस्थागत योजना के तहत डेढ़ सौ से अधिक शैक्षिक संस्थानों को भूखंड आवंटित किए गए थे।

एसटीपी का होगा निर्माण

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर के एक के समीप एसटीपी के निर्माण के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सेक्टर के एक के समीप करीब 80 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ा कर करीब 246 एमएलडी करने का भी प्रस्ताव है। इसके निर्माण होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उत्सर्जित होने वाले सीवेज का शोधन किया जाएगा। इससे खुले में बहाए जाने वाले सीवेज की भी अंकुश लगेगा।